ड्राइंग्ज पास हो गई है, बजट पास हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी साल में इन्क्लूड कराकर काम चालू करवायें ।

मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट के बढ़ने से हमें कम्युनिकेशन में प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसीलिए जब मुझे पता चला कि मनाली में एस. टी. डी. नहीं है तो हमने विशेष कदम उठाए और यह देखा कि जहां जरूरत है वहां पर आदेशों का इंतजार न किया जाए, अपने आप इनिशिएटिव लेकर अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो विभाग के और जनता के हित में है । तो इन तीनों चीजों को दिखवाकर मैं कोशिश करूंगा कि इसी 1992-93 में कंपलीट कराया जाए ।

श्री महेश्वर सिंह : मैं आप से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में और कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर हैड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है और मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जहां तक हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों का संबंध है विशेष कर लाहौलस्फीति के मुख्यालय केलंग का संबंध है वहां पर न तो सरकारी भवन पोस्ट ऑफिस के लिए है न कोई आवास की सुविधा उपलब्ध है । वे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि वर्ष में कम से कम 6 महीने तक बर्फ से लगभग ढ़के रहते हैं । तो क्या मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी विभाग को ऐसे आदेश प्रदान करेंगे कि धन का प्रावधान ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी किया जाए ताकि वहां पर भवन निर्माण का कार्य किया जा सके ?

श्री राजेश पायलट : मैडम जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है 17 हैड पोस्ट आफिसेज में से तकरीबन 15 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में है । दो जगह ऐसी हैं जहां यह काम चल रहा है—नाहन और रिकोंग पीयो । इन पर सेक्शन हो गया है । हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हमारे हैड पोस्ट ऑफिसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है । छोटे सब पोस्ट आफिसेज एक्सट्रा डिपार्टमेंटल आफिसेज ज्यादातर प्राइवेट हायर एकोमोडेशन में है । एक समस्या जो विभाग के सामने है वह यह है कि हमारा टोटल एलोकेशन 121 करोड़ का सारे देश के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में है । हर जगह से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं । क्योंकि अब रेट्स बढ़ गए हैं हमने जो डाकखाने के लिए जगह प्राइवेट हायर कर रखी है उनके मालिक पुराने रेट पर देने को तयार नहीं हैं । कहते हैं कि खाली करो । हमारे लिए उससे समस्या बनी हुई है । लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे विभाग के आफिसेज खासकर हैड आफिसेज सरकारी बिल्डिंगों में जाएं जिससे रोज-रोज लोगों की ये शिकायतें सामने न आयें ।

श्री महेश्वर सिंह : मैंने जनजाति क्षेत्र के बारे में पूछा था ।

श्री राजेश पायलट : खास जगह के लिए मैं माननीय सदस्य को अलग से इत्तला दे दूंगा ।

Government control over functioning of Foreign Banks in India

*85. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government exercises any control over functioning of foreign banks in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Foreign banks operating in the country are required to comply with the statutory requirements contained in Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Act, 1934, and other relevant statutes. The Reserve Bank of India (RBI) are responsible for supervision, control and monitoring of the functions of foreign banks as in the case of other scheduled commercial banks. The working of foreign banks in India is also reviewed by RBI each year on the basis of the information available from their balance sheets, statutory reports and other returns received from them. The foreign banks in India are inspected by RBI at intervals of two years. The system of inspection is elaborate and aims at examination of all aspects of a bank including quality of management, operational and business strategies, credit portfolios and assessment of problem credits.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Madam Deputy Chairman, I would like to know from the hon. Finance Minister, through you, whether it is a fact that most of the foreign banks fix their own rates of interest on the deposits and loans in violation of the guidelines fixed by the Reserve Bank of India thus disturbing the uniformity in the interest rates of other banks. This arbitrary functioning of the foreign banks is highly detrimental to our nationalised banks. May I know from the hon. Minister whether the Government is aware of this fact. And if so, what steps are contemplated to ensure that the Reserve Bank of India's norms are not violated?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, the foreign banks as well as the Indian banks are expected to comply with the rates of interest as stipulated by the Reserve Bank and I have not come across any violation of that by the foreign banks.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: The foreign banks, as we have observed, have a tendency to turn themselves into exclusive preserves of their vested interests in matters of recruitment, disbursement of loans and patronisation. This tendency, if not checked properly, may lead to unhealthy practices. May I know from the hon. Minister if, in keeping with his policy of openness, suitable measures are being taken to ensure that the foreign banks do not remain to be the exclusive domains of their privileged patrons but are open to the benefit of the common man of the country?

SHRI MANMOHAN SINGH: Madam, it goes without saying that the foreign banks have to function in this country within the four corners of our laws. Therefore, whatever laws we have, they have to abide by those laws.

श्री चतुरानन मिश्र : मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जानकीरमन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक जो सेक्योरिटी का बिजनैस है उसका मेज्योरिटी हिस्सा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा फोरेन बैंक्स ने हथिया लिया है तो क्या यह प्रशुभ संकेत नहीं है ?

SHRI MANMOHAN SINGH: I would say that this matter is going to be investigated. We have ordered a special audit of the four banks which account for the major proportion of this securities transaction. Until then I don't want to pass a judgement.

Reconstitution of boards of AI&IA

*86. SHRIMATI RATAN KUMARI:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Boards of Air India and Indian Airlines have been reconstituted recently; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Ratan Kumari.